

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 340
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमकेएसवाई योजना की वर्तमान स्थिति

340. श्री अनुराग शर्मा:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत कितने किसान लाभान्वित हुए हैं और इसके प्रारंभ से अब तक कुल कितने क्षेत्र को कवर किया गया है;
- (ग) वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है और अब तक निधि का कितना उपयोग किया गया है;
- (घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन में किन-किन चुनौतियाँ का सामना करना पड़ रहा है और इसके दायरे का विस्तार करने और इसकी प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए भावी योजनाएं क्या हैं; और
- (ङ) देश के कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण पर इस महत्वपूर्ण योजना का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ.): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडीएंडजीआर) तथा भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। पीएमकेएसवाई में वर्तमान में तीन घटक हैं। इन घटकों की स्थिति निम्नानुसार है;

I. पीएमकेएसवाई-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) का फोकस 2016-17 के दौरान प्राथमिकता वाले 99 चालू प्रमुख/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने पर है, साथ ही 88 परियोजनाओं में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम) का समान रूप से कार्यान्वयन भी किया जाएगा। इन परियोजनाओं में से, 63 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के एआईबीपी कार्यों को पूरा होने की सूचना दी गई है। शेष परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं की प्रगति 90% से अधिक है और 14 परियोजनाओं की प्रगति 80 से 90% के बीच है। 2016-17 से 2023-24 के दौरान इन परियोजनाओं द्वारा 19.28 लाख हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र विकास के साथ 25.80 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होने की सूचना दी गई है। वर्ष 2021-22 से नौ नई एमएमआई/विस्तार नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं को योजना में शामिल किया गया है और इन परियोजनाओं के माध्यम से 0.47 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के तहत लाभार्थियों की संख्या लगभग 2 करोड़ होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित कुल बजट 2040 करोड़ रुपये (आरई चरण) है, जिसमें से अब तक राज्यों को 692.20 करोड़ रुपये रिलीज किए जा चुके हैं।

II. पीएमकेएसवाई के हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक के अंतर्गत, 2016-17 से 2023-24 तक, सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) के अंतर्गत 3.54 लाख हेक्टेयर और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) के अंतर्गत 1.09 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित कुल बजट 598.87 करोड़ रुपये (आरई चरण) है, जिसमें से अब तक राज्यों को 453.145 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

III. वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0) के अंतर्गत 28 राज्यों में 6382 वाटरशेड विकास परियोजनाएँ कार्यान्वित की गईं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत 2021-22 से 2025-26 के दौरान 50.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 1150 परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2015-16 से अब तक इन परियोजनाओं से लगभग 46.22 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित कुल बजट 1800 करोड़ रुपये (संशोधित चरण) है, जिसमें से अब तक राज्यों को 802.42 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक पीएमकेएसवाई के हिस्से के रूप में कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के तहत 67.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिससे लगभग 63 लाख किसानों को लाभ हुआ है। पीडीएमसी के पीएम-आरकेवीवाई का हिस्सा बनने के बाद, अब तक 28.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिससे अब तक 24.35 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

(घ): पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन में एक बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण या अन्य स्थानीय भूमि से संबंधित मुद्दे रहे हैं, जिनका समाधान नियमित समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम किया गया है।

(ङ): नीति आयोग ने वर्ष 2015-2020 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई का मूल्यांकन अध्ययन किया। पीएमकेएसवाई के घटकों को प्रासंगिकता, दक्षता, प्रभाव और प्रदर्शन के समानता मापदंडों के संदर्भ में संतोषजनक माना गया है। पीएमकेएसवाई के तहत पूर्ण हो चुके वाटरशेड विकास परियोजनाओं की अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट से पता चला है कि परियोजना क्षेत्रों में सतही और भूजल की उपलब्धता, उत्पादकता में वृद्धि, वनस्पति कवर, आजीविका के अवसरों में वृद्धि और घरेलू आय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
